

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 22 —HLA of 2023

**THE HARYANA APPROPRIATION (No. 6)
BILL, 2023**

A

BILL

to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Haryana to meet the amount spent on certain services during the financial years 2019-20, 2020-21 and 2021-22 in excess of the amount authorized or granted for these services during these years.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Appropriation (No.6) Act, 2023.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana, the sums specified in column 6 of the Schedule appended to this Act, amounting in the aggregate to the sum of One Hundred Fifty-Three Crore, Thirty-Nine Lakh, Twenty-Nine Thousand, Four Hundred Sixty rupees only (₹153,39,29,460/-), Twenty-One Crore, Ninety-Two Lakh, Sixty-Three Thousand, Six Hundred Three rupees only (₹ 21,92,63,603/-) and Sixty-Three Crore, Forty-Seven Lakh, Ten Thousand, Two Hundred Forty-Six rupees only (₹ 63,47,10,246/-) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column 2 of the said Schedule during the financial years 2019-20, 2020-21 and 2021-22 respectively, in excess of the amount authorized or granted for these services during these years.

Issue of
₹153,39,29,460/- ,
₹ 21,92,63,603/- ,
and
₹ 63,47,10,246/-
out of Consolidated
Fund of State of
Haryana to meet
certain expenditure
during the years
2019-20, 2020-21
and
2021-22.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial years 2019-20, 2020-21 and 2021-22.

Appropriation.

THE SCHEDULE

2019-20

Demand No.	Services & Purposes		Sums Not Exceeding		
			Grant made by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
8	Buildings and Roads	Revenue	126,99,64,859/-	--	126,99,64,859/-
23	Food and Supplies	Revenue	26,39,64,601/-	--	26,39,64,601/-
	Grand Total		153,39,29,460/-	--	153,39,29,460/-
2020-21					
35	Tourism	Revenue	21,92,63,603/-	-	21,92,63,603/-
	Grand Total		21,92,63,603/-	-	21,92,63,603/-
2021-22					
7	Planning and Statistics	Revenue	63,43,10,825/-	-	63,43,10,825/-
23	Food and Supplies	Revenue	-	3,99,421/-	3,99,421/-
	Grand Total		63,43,10,825/-	3,99,421/-	63,47,10,246/-

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India, read with Article 205(1) thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the moneys required to meet the expenditure on account of excess over grants and appropriations for the years 2019-20, 2020-21 and 2021-22.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 18th December, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

N.B.—The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 18th December, 2023, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या-22 एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान कतिपय सेवाओं पर इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 6 में विनिर्दिष्ट राशियां, जो कुल मिलाकर केवल एक सौ तिरपन करोड़, उनतालीस लाख, उनतीस हजार, चार सौ साठ रुपए (₹ 153,39,29,460/-), केवल इक्कीस करोड़, बानवे लाख, तिरसठ हजार, छह सौ तीन रुपए (₹ 21,92,63,603/-) तथा केवल तिरसठ करोड़, सैंतालीस लाख, दस हजार, दो सौ छियालीस रुपए (₹ 63,47,10,246/-) होती हैं, क्रमशः वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्रभारों को चुकाने के लिए इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

3. इस अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने तथा उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियां, वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

संक्षिप्त नाम।

वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान कतिपय खर्च को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹ 153,39,29,460/-, ₹ 21,92,63,603/-, तथा ₹ 63,47,10,246/- का दिया जाना।

विनियोग।

अनुसूची
2019-20

मांग संख्या	सेवायें तथा प्रयोजन		अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	योग
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
8	भवन एवं सड़के	राजस्व	126,99,64,859/-	—	126,99,64,859/-
23	खाद्य एवं आपूर्ति	राजस्व	26,39,64,601/-	—	26,39,64,601/-
कुल योग			153,39,29,460/-	—	153,39,29,460/-
2020-21					
35	पर्यटन	राजस्व	21,92,63,603/-	—	21,92,63,603/-
कुल योग			21,92,63,603/-	—	21,92,63,603/-
2021-22					
7	आयोजना एवं सांख्यिकी	राजस्व	63,43,10,825/-	—	63,43,10,825/-
23	खाद्य एवं आपूर्ति	राजस्व	—	3,99,421/-	3,99,421/-
कुल योग			63,43,10,825/-	3,99,421/-	63,47,10,246/-

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसारण में वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक किए गए खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसारण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

